RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

INDORE 16 SEPTEMBER TO 22 SEPTEMBER 2020 प्रति बुधवार वर्ष 06 अंक 4 पृष्ठ 8 कीमत 5 रु.

Inside News

तेल की मांग में वृद्धि का सबसे बड़ा योगदान भारत का होगा: बीपी एनर्जी परिदृश्य Page 2

अब कारोबारियों को जीएसटी के साथ देना होगा टीसीएस Page 3

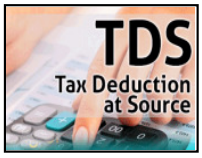

ऑनलाइन खरीदारी पर 40 से 50 फीसद तक छूट, वो भी त्योहारी सीजन में! Page 5

editoria!

कैसे काबू हो कोरोना

देश में कोरोना के तेज फैलाव के बीच शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र इस वायरस के कहर की मिसाल बन गया। सत्र शुरू होने से पहले करवाए गए कोरोना टेस्ट में 25 सांसद पॉजिटिव पाए गए। दिलचस्प मामला राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल का है जो संसद भवन में हुए टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद घर लौट गए। राजस्थान पहुंचकर उन्होंने जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में फिर से जांच करवाई तो वहां उन्हें नेगेटिव बताया गया। उन्होंने दोनों रिपोर्टों की कॉपी ट्वीट करते हुए पूछा है कि किसे सही माना जाए। सोमवार को ही दिल्ली विधानसभा का भी एकदिवसीय सत्र हुआ। उसके लिए करवाए गए टेस्ट में चार एमएलए पॉजिटिव पाए गए। लेकिन वहां की खास बात यह रही कि दो ऐसे विधायक रहे जो एंटिजन टेस्ट में नेगेटिव बताए जाने के बाद विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हुए लेकिन शाम को उनके आरटी-पीसीआर टेस्ट का रिजल्ट आया तो वे पॉजिटिव थे। उसके बाद दोनों विधायक सदन से चले गए, लेकिन दिन भर तो वे कोरोना नेगेटिव विधायक की तरह सभी गतिविधियों में शामिल रहे। इन स्थितियों ने एक बार फिर देश का ध्यान इस बात की तरफ ध्यान खींचा है कि कोरोना से निपटना तो दूर, उससे बचाव को लेकर भी कोई फूलप्रूफ प्रक्रिया हम नहीं अपना पा रहे। इसके जो दो तरह के टेस्ट प्रचलित हैं- रैपिड एंटिजन और आरटी-पीसीआर, उनमें आरटी-पीसीआर को ही भरोसेमंद माना जाता है। ब्लड सैंपल लेकर किए जाने वाले रैपिड एंटिजन टेस्ट की रिपोर्ट जल्दी आ जाती है और यह टेस्ट कम खर्चीला होता है। लेकिन इसकी रिपोर्ट की प्रामाणिकता 50 फीसदी ही बताई जाती है। आरटी-पीसीआर टेस्ट जिसमें नाक और गले से स्वैब के नमूने लिए जाते हैं, प्रामाणिक तो माना जाता है लेकिन लैब, टेक्नीशंस और मशीनों से जुड़ी सीमाओं के चलते हमारे यहां इसकी संख्या एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। इसका महंगा होना अलग समस्या है। एक टेस्ट पर करीब 4500 रुपये का खर्च आता है। शायद इसीलिए अपने देश में बड़े पैमाने पर टेस्ट करने के जो दावे विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से आ रहे हैं, वे एंटिजन टेस्ट के ही हैं। ऐसे में लगभग छह करोड़ टेस्ट के बावजूद अगर महामारी नियंत्रित होती नहीं नजर आ रही तो खास आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि महामारी के बेरोकटोक बढ़ने की खबरें सिर्फ अपने देश से नहीं आ रहीं। कई यूरोपीय देशों में इसकी दूसरी लहर चल पड़ने का खौफ दिखाई दे रहा है। इजरायल में एक बार लॉकडाउन हटा लिए जाने के बाद फिर कम से कम तीन सप्ताह के लिए इसे लागू करने का फैसला किया गया है। बहरहाल, अभी पूरी दुनिया में कोरोना का सबसे भयावह रूप हमारे यहां देखा जा रहा है और रोजाना संसार के एक तिहाई मरीज भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। 50 लाख से ऊपर कुल संक्रमण और 90 हजार प्रतिदिन नए संक्रमितों के आंकड़े हमें इस मोर्चे पर किसी भी तरह की ढिलाई की इजाजत नहीं दे रहे।

UAE और बहरीन ने इजरायल के साथ ऐतिहासिक समझौते पर किए दस्तखत

ट्रंप बोले- नए मिडल ईस्ट का आगाज

वॉशिंगटन। एजेंसी

खाड़ी देशों और इजरायल के रिश्तों में मंगलवार को एक ऐतिहासिक मोड़ की शुरुआत हुई। वाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में हुए समारोह में यूएई और बहरीन ने इजरायल के साथ ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए। समझौते के तहत खाड़ी के इन दोनों प्रमुख देशों ने इजरायल के साथ रिश्तों को पूरी तरह सामान्य करते हुए उसे मान्यता दे दी है। समझौते को अब्राहम (या इब्राहीम) संधि का नाम दिया गया है।

नए मिडल ईस्ट का आगाज: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस ऐतिहासिक समझौते को 'नए मिडल ईस्ट का आगाज' बताया है। उन्हें उम्मीद है कि इससे न सिर्फ पश्चिम एशिया में नई व्यवस्था का सूत्रपात होगा बल्कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए शबाब पर पहुंचे प्रचार के बीच उनकी छवि शांति लाने वाले एक नायक की होगी।

इजरायल को मान्यता देने वाले तीसरे और चौथे अरब देश बने यूएई, बहरीन

यूएई और बहरीन अब तीसरे और चौथे अरब देश हो गए हैं जिन्होंने 1948 में स्थापित हुए इजरायल को मान्यता दी है। दोनों देशों से पहले सिर्फ मिस्र और जॉर्डन ही ऐसे अरब देश थे जिन्होंने इजरायल को क्रमशः 1978 और 1994 में मान्यता दी थी। दशकों से ज्यादातर अरब देश इजरायल का यह कहते हुए बहिष्कार करते आए हैं कि जब तक फिलिस्तीन का विवाद हल नहीं हो जाता तब तक वे उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे।

फिलिस्तीनियों ने की निंदा, बताया खतरनाक विश्वासघात

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अध्यक्षता में हुए समारोह में यूएई और बहरीन के प्रतिनिधियों ने अलग-अलग इजरायल के प्रतिनिधि के साथ समझौते पर दस्तखत किए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समझौते का स्वागत करते हुए कहा, 'यह दिन ऐतिहासिक है। यह शांति की नई सुबह का आगाज है।' यूएई के विदेश मंत्री और वहां के ताकतवर क्राउन प्रिंस के भाई शेख अब्दुल्लाह बिन जायेद अल नाहयान ने कहा कि इससे दुनियाभर में उम्मीद की एक नई किरण जगेगी। बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लाआतिफ अल-जायानी ने भी ऐतिहासिक समझौते का स्वागत किया और साथ में यह प्रतिबद्धता भी जताई कि उनका देश फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहेगा। हालांकि, फिलिस्तीनियों ने इन समझौतों की निंदा करते हुए इसे खतरनाक विश्वासघात करार दिया है।

13 अगस्त को इजरायल और यूएई समझौते का हुआ था ऐलान

13 अगस्त को इजरायल- यूएई समझौते की घोषणा की गई थी जबकि इजरायल बहरीन समझौते का ऐलान पिछले हफ्ते किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर इन ऐतिहासिक समझौतों की नींव पड़ी। इसके पीछे ट्रंप के सलाहकार और दामाद जेरेड कुशनर ने भी अहम भूमिका निभाई। यूएई और बहरीन के नेताओं से फोन पर बात करने के बाद ट्रंप ने खुद दोनों समझौतों की घोषणा की थी।

कच्चे तेल में दूसरे दिन तेजी जारी डीजल के दामों पर लगा ब्रेक

नई दिल्ली। एजेंसी

तूफान के चलते अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन प्रभावित होने और तेल का भंडार घटने के अनुमानों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बुधवार को लगातार दूसरे दिन तेल की कीमतों में तेजी जारी रहा। वहीं, भारत में बीते दो दिनों से जारी पेट्रोल और डीजल के दाम में गिरावट पर ब्रेक लग गया है। तेल विपणन कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि एक दिन पहले पेट्रोल के दाम में दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 17 पैसे, जबकि चेन्नई में 15 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई थी। वहीं, डीजल के दाम में दिल्ली और कोलकाता में 22 पैसे जबकि मुंबई में 24 पैसे और चेन्नई में 21 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई थी।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल का दाम बिना किसी बदलाव के क्रमशः 81.55 रुपये, 83.06 रुपये, 88.21रुपये और 84.57 रुपये प्रति लीटर पर बना हुआ है। डीजल की कीमत भी चारों महानगरों में क्रमशः 72.56 रुपये, 76.06 रुपये, 79.05 रुपये और 77.91 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बनी हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटर कांटिनेंटल एक्सचेंज (आईसीई) पर ब्रेंट क्रूड के नवंबर डिलीवरी अनुबंध में बुधवार को पिछले सत्र के मुकाबले 1.48 फीसदी की तेजी के साथ 41.13 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। पिछले सत्र में ब्रेंट क्रूड का सबसे सक्रिय वायदा अनुबंध 2.65 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ था।

वहीं, न्यूयार्क मर्केंटाइल एक्सचेंज (नायमैक्स) पर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) के अक्टूबर डिलीवरी वायदा अनुबंध में पिछले सत्र के मुकाबले 1.75 फीसदी की तेजी के साथ 38.95 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। डब्ल्यूटीआई का भाव बीते सत्र में 3.38 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ था। जानकारों ने बताया कि मेक्सिको की खाड़ी में तूफान सैली के कारण तेल का उत्पादन प्रभावित होने से कीमतों में तेजी आई है। वहीं, अमेरिकी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका मे बीते सप्ताह तेल के भंडार में 95 लाख बैरल की गिरावट आई है। हालांकि बाजार को बुधवार को जारी होने वाले अमेरिकी एजेंसी एनर्जी इन्फोरमेशन एडमिनिस्ट्रेशन के आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार है। केडिया ने कहा कि चीन में औद्योगिक उत्पादन और खुदरा बिक्री के अच्छे आंकड़े आने और जर्मन बिजनेस कान्फिडेंस में सुधार की रिपोर्ट से भी कच्चे तेल की तेजी को सपोर्ट मिल रहा है।

वायदा बाजार में कच्चा तेल 44 रुपये मजबूत

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

हाजिर मांग में तेजी के साथ सटोरियों के सौदा बढ़ाये जाने से वायदा बाजार में कच्चा तेल बुधवार को 44 रुपये मजबूत होकर 2,872 रुपये प्रति बैरल पर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सितंबर महीने की डिलिवरी के लिये कच्चा तेल 44 रुपये यानी 1.56 प्रतिशत बढ़कर 2,872 रुपये प्रति बैरल पर पहुंच गया। इसमें 4,307 लॉट के लिये कारोबार हुआ। विश्लेषकों के अनुसार प्रतिभागियों के सौदा बढ़ाये जाने से कच्चे तेल के दाम में तेजी आयी। वैश्विक स्तर पर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड का भाव 2.80 प्रतिशत बढ़कर 39.35 डॉलर प्रति बैरल रहा। वहीं न्यूयार्क में ब्रेंट क्रूड का भाव 2.49 प्रतिशत बढ़कर 41.54 डॉलर प्रति बैरल दर्ज किया गया।

कोरोना संकट के दौर में मददगार बना ईपीएफओ

4 महीनों में करीब 442 करोड़ रुपये पीएफ का भुगतान किया

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना महामारी के चलते पैदा हुए आर्थिक संकट के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आम लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है। उद्योग-धंधे चौपट होने और रोजगार छिनने के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने पीएफ का सहारा लिया और खातों में जमा पूंजी निकालकर जीवनयापन कर रहे हैं। वहीं कई कंपनियों द्वारा समय से राशि जमा नहीं किए जाने से पीएफ विभाग की परेशानी बढ़ी है।

लॉकडाउन में बढ़ गए आवेदन

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-2 सुशांत कंडवाल के अनुसार एक अप्रैल से 31 अगस्त तक करीब एक लाख 60 हजार से ज्यादा लोगों ने पीएफ राशि निकालने के लिए आवेदन किया। इन सभी के एडवांस क्लेम का विभाग ने निपटारा किया। करीब 442 करोड़ से ज्यादा राशि आवंटित की गई। पिछले सालों की तुलना में यह आंकड़ा बहुत अधिक है। उन्होंने बताया कि कोरोना संकट से पहले इतने आवेदन नहीं आए थे। सुशांत कंडवाल ने बताया कि एक जनवरी 2020 से 31 मार्च के बीच करीब 70 हजार लोगों ने 218 करोड़ की जमा राशि निकाली। जबकि लॉकडाउन के बाद यह राशि दोगुनी से ज्यादा हो गई।

क्यों बढ़े आवेदन

लॉकडाउन में एक ओर जहां कई लोगों की नौकरियां चली गईं, वहीं कम वेतन मिलने या समय पर नहीं मिलने संबंधी परेशानियां भी आईं। ऐसे में पैसों की जरूरत पड़ने पर लोग पीएफ का सहारा ले रहे हैं। बदली परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने पीएफ निकासी के नियमों में भी छूट दी है।

ढाई हजार कंपनियों ने जमा नहीं की राशि

जहां पीएफ निकालने वालों की संख्या बढ़ी है वहीं जिले की छोटी कंपनियों द्वारा समय से पीएफ भुगतान नहीं करना विभाग के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। कोरोना काल के दौरान नोएडा की करीब ढाई हजार कंपनियों ने कर्मचारियों की पीएफ राशि जमा नहीं कराई है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-2 ने बताया कि ऐसी कंपनियों को नोटिस भेजे गए हैं।

तेल की मांग में वृद्धि का सबसे बड़ा योगदान भारत का होगाः बीपी एनर्जी परिदृश्य

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत 2050 तक ऊर्जा के लिये मांग का सबसे बड़ा स्रोत होगा जबकि वैश्विक स्तर पर जो निरंतर वृद्धि हो रही थी, उस पर अंकुश लगेगा। बीपी पीएलसी ने सोमवार को सालाना ऊर्जा परिदृश्य 2020 में यह बात कही। वहीं तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने कहा कि विकासशील देशों को कोरोना वायरस महामारी को रोकने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे वैश्विक स्तर पर खासकर भारत में तेल मांग पर असर पड़ेगा। बीपी की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर तेल खपत कोरोना वायरस संकट के पहले के स्तरों पर संभवतः कभी नहीं लौटे। रिपोर्ट में तीन परिदृश्यों पर विचार किया गया है - 'रैपिड' दृष्टिकोण के तहत नए नीतिगत उपायों से कार्बन की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जबकि शुद्ध कार्बन उत्सर्जन शून्य करने की पहल 'नेट जीरो' से सामाजिक व्यवहार में बड़े स्तर पर बदलाव आएगा। वहीं मौजूदा गतिविधियों को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि सरकार की नीतियां, तकनीक और सामाजिक प्राथमिकताएँ पूर्व की तरह आगे बढ़ती रहेंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि तीनों परिदृश्य में भारत 2050 तक मांग में वृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत होगा। इसमें कहा गया है कि भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत 2018 से 2050 के दौरान 2.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। यह चीन के मामले में 0.1 प्रतिशत और वैश्विक स्तर पर 0.3 प्रतिशत के मुकाबले बेहतर है। इस बीच, ओपेक ने कहा कि विकासशील देशों को कोरोना वायरस महामारी को रोकने में समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इससे वैश्विक स्तर पर खासकर भारत में तेल की मांग में कमी आएगी।। ओपेक ने इस साल और अगले साल के लिये वैश्विक मांग में 400,000 बैरल प्रतिदिन की कमी का अनुमान को संशोधित किया है। नये अनुमान के अनुसार अब इसमें 2020 में 95 लाख बैरल प्रतिदिन और 2021 में 66 लाख बैरल प्रतिदिन की कमी आएगी।

प्रमुख बंदरगाहों की माल ढुलाई अप्रैल-अगस्त में 16.56 प्रतिशत घटकर 24.5 करोड़ टन

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश के प्रमुख बंदरगाहों की माल ढुलाई (माल चढ़ाना उतारना) चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से अगस्त की अवधि के दौरान 16.56 प्रतिशत घटकर 24.50 करोड़ टन रह गई। केंद्र के नियंत्रण वाले इन 12 प्रमुख बंदरगाहों में से मोर्मुगाव को छोड़कर अन्य सभी की माल ढुलाई में अगस्त में लगातार पांचवें महीने गिरावट आई है। भारतीय बंदरगाह संघ (आईपीए) के ताजा आंकड़ों के अनुसार इन 12 बंदरगाहों की माल ढुलाई पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 29.36 करोड़ टन रही थी। अप्रैल-अगस्त के दौरान चेन्नई, कोचीन और कामराजार बंदरगाहों की ढुलाई में 30 प्रतिशत की गिरावट आई। वहीं जेएनपीटी और कोलकाता बंदरगाहों की ढुलाई 20 प्रतिशत से अधिक घटी। देश में केंद्र के नियंत्रण वाले 12 प्रमुख बंदरगाहों में दीनदयाल (पूर्ववर्ती कांडला), मुंबई, जेएनपीटी, मोर्मुगाव, न्यू मंगलूर, कामराजार (पूर्व में एन्नोर) कोचीन, चेन्नई, वी ओ चिदंबरनार, विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता (हल्दिया सहित) शामिल हैं। अप्रैल से अगस्त के दौरान कामराजार बंदगाह की ढुलाई 31.64 प्रतिशत घटकर 91.1 लाख टन रह गई । चेन्नई बंदरगाह की ढुलाई 30.36 प्रतिशत घटकर 1.44 करोड़ टन रही। वहीं कोचीन बंदरगाह की ढुलाई में 29.88 प्रतिशत की गिरावट आई और यह एक करोड़ टन से कुछ अधिक रही। इस अवधि में जेएनपीटी बंदरगाह की ढुलाई 25.53 प्रतिशत घटकर 2.16 करोड़ टन, कोलकाता की 23.74 प्रतिशत घटकर 2.06 करोड़ टन रही। मुंबई बंदरगाह की ढुलाई 19.31 प्रतिशत घटकर 2.01 करोड़ टन पर आ गई।

अप्रैल-जून में भारत-चीन व्यापार घाटा कम हुआ : सरकार

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कम होकर 5.48 अरब डॉलर हो गया जो पिछले साल इसी अवधि में 13.1 अरब डॉलर था। सरकार ने बुधवार को संसद में यह जानकारी दी। लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार भी 2020-21 के पहले तीन महीने में कम होकर 16.55 अरब डॉलर रह गया जो पिछले साल इसी अवधि में 21.42 अरब डॉलर था। उन्होंने कहा, "सरकार ने चीन को निर्यात बढ़ाकर और चीन से आयात पर हमारी निर्भरता कम करके उसके साथ व्यापार संतुलन के लिए लगातार कदम उठाये हैं।"

अगस्त में आयात-निर्यात घटे, व्यापार घाटा गिर कर रह गया 6.77 अरब डॉलर

नयी दिल्ली। पिछले महीने देश के निर्यात में लगातार छठे महीने गिरावट आई। अगस्त 2019 के मुकाबले अगस्त 2020 में भारत का निर्यात 12.66 फीसदी की गिरावट के साथ 22.7 अरब डॉलर रह गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पेट्रोलियम, चमड़ा, इंजीनियरिंग सामान और रत्न और आभूषण वस्तुओं की शिपमेंट में कमी आने से निर्यात घटा। बता दें कि निर्यात में जून और जुलाई के मुकाबले ज्यादा गिरावट आई है। साल दर साल आधार पर जून में देश का निर्यात 12.41 फीसदी और जुलाई में 10.21 फीसदी घटा था। अगस्त 2019 में भारत का निर्यात 25.99 अरब डॉलर का रहा था। मालूम हो कि अगस्त में भारत के आयात में भी गिरावट आई है, जबकि व्यापार घाटा भी घटा है।

कितना घटा आयात

आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2019 की तुलना में पिछले आयात 26 फीसदी घट कर 29.47 अरब डॉलर रह गया। इससे ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा भी 6.77 अरब डॉलर रह गया। व्यापार घाटा जुलाई 2020 के मुकाबले कम रहा है। जुलाई में व्यापार घाटा (आयात और निर्यात के बीच का अंतर) 4.83 अरब डॉलर था। ऑयल आयात 41.62 फीसदी लुढ़क कर 6.42 अरब डॉलर रह गया। वहीं सोना आयात पिछले साल समान में 1.36 अरब डॉलर के मुकाबले उछल कर 3.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया। अप्रैल-अगस्त (चालू वित्त वर्ष की अवधि में अब तक) की अवधि के दौरान निर्यात 26.65 प्रतिशत घट कर 97.66 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 43.73 प्रतिशत घट कर 118.38 डॉलर रहा। जबकि इस दौरान व्यापार घाटा 20.72 अरब डॉलर का रहा।

अगस्त में किसका निर्यात कितना घटा

अगस्त के दौरान प्रमुख निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद (40 प्रतिशत), रत्न और आभूषण (43.28 प्रतिशत), चमड़ा (16.82 प्रतिशत), मानव निर्मित यार्न / फैब्स / मेड-अप (24.23 प्रतिशत), सभी टेक्सटाइल के तैयार वस्त्र (14 प्रतिशत) और इंजीनियरिंग (7.69 प्रतिशत) के निर्यात में गिरावट आई। पिछले महीने के दौरान जिन चीजों का निर्यात बढ़ा उनमें चावल, कॉफी, तंबाकू, लौह अयस्क, ऑयल सीड, ऑयल मील्स, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स और प्लास्टिक शामिल हैं।

किन चीजों का आयात घटा

अगस्त में जिन चीजों का आयात घटा उनमें मशीनरी, विद्युत और गैर-विद्युत, रसायन, लकड़ी और इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल हैं। अप्रैल-अगस्त की अवधि के दौरान तेल आयात 53.61 प्रतिशत घट कर 26 अरब डॉलर रह गया। गैर-तेल उत्पादों का आयात 40 प्रतिशत की गिरावट के साथ 92.35 अरब डॉलर हो गया। जानकार कहते हैं कि आयात का विश्लेषण करने की आवश्यकता है, क्योंकि आयात में इतनी गिरावट आने वाले महीनों में औद्योगिक सुधार में बाधा बन सकती है। इस बीच एक वेबिनार में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सितंबर के दूसरे सप्ताह (8-14) के दौरान निर्यात 10.73 प्रतिशत बढ़कर 6.88 अरब डॉलर हो गया।

अब कारोबारियों को जीएसटी के साथ देना होगा टीसीएस

रायपुर। एजेंसी

अक्टूबर से टैक्स नियमों में कुछ बदलाव होने वाला है। बदलाव के संबंध में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। विशेषकर ऐसे कारोबारी, जिनका सालाना टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक होता है, वे बदलाव के बारे में अच्छी तरह जान लें। अब इन कारोबारियों को जीएसटी के साथ ही टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स भी देना होगा। हालांकि टीसीएस काफी कम है, लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है।

कर विशेषज्ञों से मिली जानकारी के अनुसार कारोबारियों को जीएसटी के साथ टीसीएस के रूप में 0.1 फीसद चुकाना होगा यानी आपका टर्नओवर 20 करोड़ माना जाए तो आपको करीब दो लाख का टीसीएस देना होगा। कर विशेषज्ञ व आयकर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष चेतन तारवानी ने बताया कि अक्टूबर से ऐसे कारोबारियों के लिए जीएसटी के साथ टीसीएस भी पटाना अनिवार्य होगा।

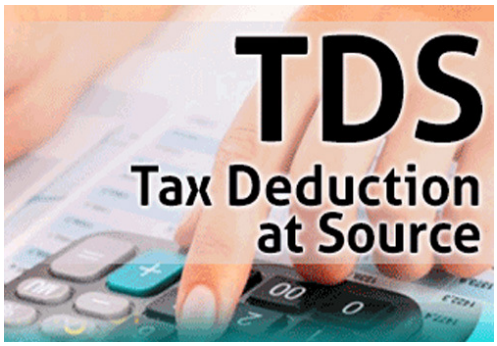

टीडीएस

यह आपकी इनकम के स्रोत यानी आपकी सैलरी से कटता है। टीडीएस इनकम टैक्स का ही एक हिस्सा होता है। इसका भुगतान टैक्स पेयर पहले ही कर चुका होता है। इसका सेटलमेंट इनकम टैक्स रिटर्न आइटीआर भरने के दौरान कर दिया जाता है। अगर आपके वेतन से कटा टीडीएस आपकी कुल टैक्स देनदारी से ज्यादा होता है तो वह आपको आइटीआर फाइलिंग के जरिए वापस कर दिया जाता है। कुल मिलाकर यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जिसके जरिए सरकार टैक्स को तुरंत इकट्ठा करती है।

कौन देता है टीडीएस

पेमेंट करने वाले व्यक्ति या संस्था कंपनी पर टीडीएस भरने की जिम्मेदारी होती है। इन्हें डिडक्टर कहा जाता है। वहीं टैक्स काटकर भुगतान हासिल करने वाले को डिडक्टी कहते हैं। टीडीएस के रूप में काटी गई रकम को सरकार के खाते में जमा करना जरूरी है।

टीसीएस

टीसीएस का मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है। यह स्रोत पर एकत्रित टैक्स इनकम से इकट्ठा किया गया टैक्स होता है। टीसीएस का भुगतान सेलर, डीलर, वेंडर, दुकानदार की तरफ से किया जाता है। हालांकि वह कोई भी सामान बेचते हुए खरीदार या ग्राहक से वसूलता है। वसूलने के बाद इसे जमा करने का काम सेलर या दुकानदार का ही होता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 206भ में इसे कंट्रोल किया जाता है। कुछ खास तरह की वस्तुओं के विक्रेता ही इसे कलेक्ट करते हैं। इन वस्तुओं में टिंबर वुड, स्क्रैप, मिनरल, तेंदु पत्ते शामिल हैं।

25 सितंबर से लागू होगी फेसलेस अपील

इसके साथ ही इस महीने 25 सितंबर से ही फेसलेस अपील लागू होने वाली है। इसके लागू होने के बाद आयकर में और भी ज्यादा पारदर्शिता आ जाएगी और किसी भी प्रकार से जान-पहचान या रिश्तेदारी काम नहीं आएगी। फेसलेस अपील में आपके द्वारा की गई अपील किस स्थान पर जा रही है और किसके पास जा रही है, आपको मालूम नहीं होगा। इसी प्रकार अधिकारी को भी आपके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी।

पांच अक्तूबर तक टली GST परिषद की 42वीं बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

जीएसटी परिषद की बैठक पांच अक्तूबर तक टल गई है। पहले यह बैठक 19 सितंबर को होनी थी। इस संदर्भ में सूत्रों ने बताया कि परिषद की 42वीं बैठक को टाल दिया गया है, क्योंकि उस दौरान संसद का सत्र चल रहा होगा। केंद्र ने पिछले महीने फैसला किया था कि जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक 19 सितंबर को होगी। उस समय तक संसद के मानसून सत्र पर फैसला नहीं हुआ था।

महत्वपूर्ण होगी बैठक

जीएसटी परिषद की पांच अक्तूबर को होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी संग्रहण में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी के वित्तपोषण के मुद्दे पर विवाद चल रहा है। केंद्र की गणना के अनुसार इसमें से 97,000 करोड़ रुपये की कमी जीएसटी के कार्यान्वयन से जुड़ी है। शेष 1.38 लाख करोड़ रुपये की कमी राज्यों के राजस्व पर कोविड-19 के प्रभाव की वजह से है।

केंद्र ने दिए थे दो विकल्प

केंद्र ने पिछले महीने राज्यों को रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सुविधा के जरिए 97,000 करोड़ रुपये का कर्ज जुटाने या बाजार से 2.35 लाख करोड़ रुपये जुटाने के दो विकल्प दिए थे। इसके अलावा केंद्र ने विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर मुआवजा उपकर को 2022 से आगे बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया था, जिससे राज्य कर्ज का भुगतान कर सकें।

छह गैर-भाजपा शासित राज्यों- पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु ने केंद्र को पत्र लिखकर राज्यों द्वारा कर्ज लेने के विकल्प का विरोध किया था। सूत्रों ने बताया कि आठ सितंबर तक सात राज्य अपनी पसंद के विकल्प के बारे में केंद्र को सूचित कर चुके हैं। गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और त्रिपुरा ने 97,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने का विकल्प चुना है। वहीं सिक्किम और मणिपुर ने दूसरा 2.35 लाख करोड़ रुपये बाजार से जुटाने वाले कर्ज का विकल्प चुना है।

खाद्य, पेय पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने के बारे में उपाय सुझाने को लेकर समितियों का गठन

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद (टीपीसीआई) ने मंगलवार को कहा कि उसने खाद्य, रसायन और खाद्य प्रसंस्करण तथा पेय पदार्थों के निर्यात को गति देने के बारे में उपाय सुझाने को लेकर तीन समितियों का गठन किया है। ये समितियां अपनी सिफारिशें सरकार को देंगी। समितियों का गठन खाद्य एवं पेय पदार्थ, खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी और रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्षेत्रों के लिये किया गया है। टीपीसीआई ने एक बयान में कहा कि ये समितियां एक शोध संस्थान के रूप में काम करेंगी और निर्यात को बढ़ावा देने को लेकर अपने सुझाव तथा सिफारिशें सरकार को देंगी। बयान के अनुसार खाद्य एवं पेय पदार्थों पर गठित समिति के अध्यक्ष रामदेव फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लि. के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मामलों के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौड़ होंगे। वहीं खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी पर गठित समिति की अगुवाई आईटीसी लि. के सीईओ (प्रिंटिंग एवं पैकेजिंग इकाई) आर सेनगुत्तुवन करेंगे।

Work From Home बढ़ा सकता है Tax का बोझ, जानिए कैसे

नयी दिल्ली। कोरोना संकट के चलते बड़ी संख्या में लोग घरों से काम कर रहे हैं। घर से काम करते हुए कई महीने बीच चुके हैं। अभी कब तक ऐसा चलेगा इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। पर क्या आप जानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करना आपकी टैक्स देनदारी बढ़ा सकता है। आइए जानते हैं कैसे। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप पिछले कुछ महीनों से सामान्य से अधिक बचत कर रहे हैं। इससे बहुत कुछ पता चलता है। घर से काम करते समय कर्मचारी अधिक बचत करने में सक्षम हैं क्योंकि इसमें ट्रेवल या खाने पर ज्यादा खर्च नहीं होता। मगर इसी से आपकी जेब पर असर पड़ सकता है क्योंकि ज्यादा बचत ज्यादा टैक्स की देनदारी ला सकती है।

इन चीजों पर लग सकता है टैक्स

यदि आपको नहीं पता तो बता दें कि आपकी कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने वाले वेतन में कई चीजें शामिल होती हैं। इनमें कनवेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और लीव ट्रैवल अलाउंस (एलटीए) शामिल हैं। अगर आप घर पर रह रहे हैं और बिल्कुल यात्रा नहीं कर रहे हैं तो इन सभी पर टैक्स लगने की संभावना है। कर्मचारी रोज ऑफिस नहीं जा रहे हैं इसलिए कनवेंस अलाउंस टैक्स फ्री नहीं रह सकता। जब कनवेंस अलाउंस प्रतिपूर्ति (रिम्बर्सेलसहू) के रूप में दिया जाए तो यह टैक्स फ्री तब ही होगा आप वास्तव में खर्च उठाएं और उसके प्रूफ पेश करें। रोजाना ट्रेवल न होने की स्थिति में इस भत्ते पर टैक्स लग सकता है।

घर के किराये पर मिलने वाले भत्ते पर टैक्स

पिछले 5 महीनों में ट्रांसपोर्ट के ज्यादातर मॉड बंद हैं। इसलिए आपने पिछले पांच महीनों में सफर भी नही किया होगा, जिसका मतलब है कि आप चालू वित्तीय वर्ष के लिए एलटीए का क्लेम करने के पात्र नहीं होंगे। एलटी पर भी टैक्स सकता है। यहां बताई जाने वाली बात यह है कि चार साल के ब्लॉक में दो बार एलटीए का क्लेम किया जा सकता है। आखिर में अगर आप किराए के मकान में रह रहे थे और कोरोना संकट में अपने गृह राज्य में वापस जाकर वहां घर से काम करने लगे हैं तो आप एचआरए (हाउस रेंट अलाउंट) पर बचत नहीं कर पाएंगे। आप किराए की रिसीट पेश नहीं कर सकेंगे, जिससे आपको इस पर टैक्स की बचत नहीं होगी।

इस पैसे पर भी टैक्स

कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को वर्क होम अलाउंट, बिजली, लैपटॉप खरीदने और घर में ऑफिस बनाने के लिए फर्नीचर खरीदने जैसे खर्चों को पूरा करने के लिए एक निश्चित राशि दे रही हैं, जिसके लिए आपको बिल पेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामले में ये राशि कर्मचारियों के हाथों में कर योग्य होगी।

10 हजार या इससे ज्यादा रकम एटीएम से निकालने के लिए SBI ने बदले नियम

नई दिल्ली। एजेंसी

डेबिट या एटीएम कार्ड (Debit or ATM Card) से पैसे निकालने में बढ़ रही धोखाधड़ी की घटना पर लगाम लगाने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक, एसबीआई (State Bank of India) ने एक बड़ा फैसला किया है। अब इसके एटीएम (SBI ATM) से 10 हजार रुपये या इससे अधिक राशि निकालने पर दिन में भी ओटीपी (OTP) की आवश्यकता होगी। अभी तक रात में आठ बजे से सुबह आठ बजे इतनी रकम निकालने पर ही ओटीपी की जरूरत होती थी। यह व्यवस्था आगामी 18 सितंबर से देश भर में लागू हो रही है। इसके साथ ही बैंक ने अपने सभी ग्राहकों से मोबाइल नंबर अपडेट (Update your Mobile number) करवाने को कहा है।

एटीएम सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए हो रहा है ऐसा

एसबीआई (SBI) से मिली सूचना के अनुसार बैंक ने अपने एटीएम की सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए ऐसा किया है। देश के सबसे बड़े ऋणदाता, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 1 जनवरी, 2020 से एँ एटीएम के माध्यम से रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच 10,000 रुपए और उससे ऊपर के ध्ऊइ आधारित नकद निकासी की शुरुआत की थी। अब देश के सभी एसबीआई एटीएम में ओटीपी आधारित एटीएम निकासी की व्यवस्था पूरे दिन और रात के लिए लागू कर दी है। मतबल अब 24 घंटे इसकी जरूरत होगी। यह व्यवस्था 18 सितंबर, 2020 से लागू होगी। 10,000 रुपए और इससे अधिक की निकासी पर अपने डेबिट कार्ड पिन के साथ अपने पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करना होगा।

धोखेबाजों से होगा बचाव

एसबीआई के एमडी (रिटेल और डिजिटल बैंकिंग), सी एस सेट्टी का कहना है कि 24x7 ओटीपी-आधारित नकदी निकासी सुविधा की शुरुआत के साथ, एसबीआई ने एटीएम नकदी निकासी में सुरक्षा स्तर को और मजबूत कर दिया है। दिन भर इस सुविधा को लागू करने से एसबीआई डेबिट कार्डधारक धोखेबाजों, अनधिकृत निकासी, कार्ड स्किमिंग, कार्ड क्लोनिंग और इसी तरह के जोखिम से बच सकेंगे।

मोबाइल नंबर अपडेट करायें

एसबीआई का कहना है कि जो ग्राहक अक्सर 10 हजार रुपये या इससे ज्यादा रकम की निकासी करते हों, वे बैंक में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराएं। अक्सर देखा गया है कि पहले ग्राहक खाता खुलवाते समय मोबाइल नंबर नहीं देते थे। किसी ने कोई नंबर दिया भी है तो वह इन दिनों काम नहीं करता। इसलिए ग्राहकों से निवेदन किया गया है कि जो नंबर चल रहा हो, उसे बैंक खाता से जोड़ें।

क्या है ओटीपी

ओटीपी दरअसल एक सिस्टम-जनरेटेड न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, जो यूजर के लिए एकल लेन-देन को प्रमाणित करता है। ग्राहक जब एटीएम के माध्यम से रकम को निकालना चाहेगा, तो एटीएम स्क्रीन ओटीपी मांगेगी। वहां उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त किए गए ओटीपी को दर्ज करना होगा। यदि स्क्रीन पर सही ओटीपी दिया जाएगा, तभी एटीएम पिन दर्ज करेगा। ओटीपी आधारित नकद निकासी की सुविधा केवल एसबीआई एटीएम में उपलब्ध है। एसबीआई का कहना है कि दूसरे बैंकों के एटीएम में यह कार्यक्षमता नेशनल फाइनेंशियल स्विच (NFS) में विकसित नहीं की गई है।

भारत में घट गए मकानों के रेट, मूल्य वृद्धि रैंकिंग में रहा 54वां स्थान

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना काल में वैसे तो सभी सेक्टर पर मार पड़ी है पर इससे अछूता रियलटी सेक्टर भी नहीं रहा। भारत में मकानों के भाव गिर गए। मकानों की कीमत वृद्धि के मामले में भारत की रैंकिंग अप्रैल-जून तिमाही में 11 स्थान गिरकर 54 रह गई। इस तिमाही के दौरान भारत में मकानों के दाम पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले करीब दो फीसद नीचे आ गए। इससे पहले 2020 की पहली तिमाही जनवरी-मार्च में भारत 43वें स्थान पर था।

वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी नाइट फ्रैंक की 'ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स अप्रैल-जून 2020 में 56 देशों की रैंकिंग की गई है। रिपोर्ट में देश की रैंकिंग गिरने की बड़ी वजह अप्रैल-जून तिमाही में आवासों की कीमत पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 1.9 फीसद गिरना बताई गई है। वर्ष 2019 की इसी अवधि से तुलना करने पर वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में वार्षिक रैंकिंग में तुर्की सबसे ऊपर रहा। यहां आवास कीमत में सालाना आधार पर 25.7 फीसद की बढ़त देखी गई। इसके बाद 13.9 फीसद की वृद्धि के साथ लक्जमबर्ग और 12.4 फीसद की बढ़त के साथ लिथुआनिया तीसरे स्थान पर रहा।

समीक्षावधि में सबसे बुरा प्रदर्शन हांगकांग का रहा। यहां आवास की कीमत में सालाना आधार पर 2.8 फीसद की गिरावट रही। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिशिर बैजल ने कहा कि देश के अधिकतर बाजारों में आवास क्षेत्र कमजोर मांग से जूझ रहा है। कोविड-19 महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था में नरमी ने रियल एस्टेट क्षेत्र पर बुरा असर डाला है। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वेक्षण में शामिल देशों में से 9 फीसद में सालाना आधार पर मकानों के दाम घटे हैं। शीर्ष स्थान पाने वाले दस देशों में से आठ स्थान यूरोपीय देशों को मिले हैं।

रोबोट करेंगे होम डिलीवरी!, स्नैपडील ने शुरू किया परीक्षण

नयी दिल्ली। एजेंसी

अमेजन और वालमार्ट जैसी ई-वाणिज्य कंपनियां जब डिलीवरी के लिए ड्रोन का विकल्प आजमा रही हैं तब घरेलू ई-वाणिज्य कंपनी स्नैपडील ने रोबोट के माध्यम से डिलीवरी का परीक्षण शुरू किया है, ताकि ग्राहकों को उनके घर तक संपर्क रहित डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। स्नैपडील ने एक बयान में कहा कि इसके लिए उसने स्टार्टअप कंपनी ऑटोनॉमी आईओ के साथ गठजोड़ किया है। दोनों ने मिलकर दिल्ली-एनसीआर के कुछ चुनींदा स्थानों पर रोबोट के माध्यम से डिलीवरी का सफल परीक्षण किया है।

कैसे काम करता है यह रोबोट

बयान के मुताबिक डिलीवरी करने वाले रोबोट को सोसायटी के गेट पर रखा गया। जहां डिलीवरी एजेंट क्यूआर कोड स्कैन करता है और पैकेट को रोबोट के अंदर रख देता है। रोबोट के पास सोसायटी का मानचित्र होता है और वह उसके सहारे ग्राहक तक सामान की डिलीवरी कर देता है। बयान के मुताबिक ऑटोनॉमी आईओ ने अंतिम छोर तक डिलीवरी देने के लिए इन रोबोट को विकसित किया है।

यह सड़क पर फुटपाथ पर खुद से चल सकते हैं। इनमें भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सही से चलने के लिए विशेष कृत्रिम मेधा को विकसित किया गया है। साथ ही यह मशीन लर्निंग का भी उपयोग करते हैं। इनमें कैमरा है जो उन्हें बाहरी दुनिया को समझने में मदद करता है। हाल में वालमार्ट ने अमेरिका में ड्रोन से उत्पादों की डिलीवरी करने के लिए जिपलाइन और फ्लाईट्रेक्स के साथ साझेदारी की घोषणा की थी। अमेजन की भी डिलीवरी करने के लिए ड्रोन के उपयोग की योजना है।

डाबर उतरी खाद्य तेल बाजार में

नयी दिल्ली। एजेंसी

आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने वाली कंपनी डाबर इंडिया ने सोमवार को कच्ची घानी (कोल्ड प्रेस्ड) सरसों का तेल बाजार में पेश किया। इसी के साथ कंपनी ने खाद्य तेल बाजार में उतरने की घोषणा की है। डाबर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहित मल्होत्रा ने कहा, " डाबर कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल की बाजार में पेशकश हमारी भारत में अपने खाद्य कारोबार को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है।" कंपनी ने इसे अमेजन और मिल्कबास्केट ई-वाणिज्य मंच पर ही पेश किया है। कोल्ड प्रेस्ड तकनीक में तेल का उत्पादन सामान्य तापमान पर होता है। इससे तेल में अम्ल की मात्रा बढ़ती नहीं और उसे फिल्टर नहीं करना पड़ता।

सरकार ने चर्म उद्योग के लिये विकास परिषद का गठन किया

नयी दिल्ली। सरकार ने जूता-चप्पल और चमड़ा उद्योग के लिये 25 सदस्यीय विकास परिषद का गठन किया है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की अधिसूचना के अनुसार परिषद का गठन दो साल के लिये किया गया है। परिषद के चेयरमैन एक्शन शूज के प्रबंध निदेशक राज कुमार गुप्ता हैं। परिषद के सदस्यों में चमड़ा निर्यात परिषद के चेयरमैन, नोएडा स्थित फूटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के प्रबंध निदेशक, चेन्नई स्थित केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान के निदेशक और आगरा फूटवियर मैनुफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स चैंबर के अध्यक्ष शामिल हैं।

67 फीसद खिलौने सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे, गुणवत्ता नियमों को लागू करने की समय सीमा बढ़ी

नयी दिल्ली। एजेंसी

मोदी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच गुणवत्ता मानकों को लागू करने के लिए घरेलू खिलौना उद्योग को अगले साल जनवरी तक चार और महीनों की मोहलत दी है। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने अधिसूचना जारी कर खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2020 के कार्यान्वयन की तारीख को इस साल एक सितंबर से बढ़ाकर एक जनवरी 2021 कर दिया है।

बाजार में घटिया मानक वाले खिलौनों पर लगेगी रोक

आदेश में कहा गया कि इस निर्णय के तहत घरेलू विनिर्माताओं को कोविड-19 महामारी से पैदा हुई कठिनाइयों के मद्देनजर मानकों को लागू करने के लिए चार महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। सरकार इस समय खिलौनों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है और उसने फरवरी में खिलौनों के आयात शुल्क में बढ़ोतरी भी की थी। खिलौनों के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से सरकार ने बाजार में घटिया मानक वाले खिलौनों पर रोक लगाने की कोशिश की है।

4,000 से अधिक छोटे और मझोले उद्योग

एक अध्ययन के अनुसार लगभग 67 प्रतिशत खिलौने सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे। भारत में खिलौने उद्योग मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में है, जिसमें लगभग 4,000 से अधिक छोटे और मझोले उद्योग शामिल हैं। भारत में लगभग 85 प्रतिशत खिलौने चीन से आयात किए जाते हैं। इसके बाद श्रीलंका, मलेशिया, जर्मनी, हांगकांग और अमेरिका का स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में भारत में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही थी।

ऑनलाइन खरीदारी पर 40 से 50 फीसद तक छूट, वो भी त्योहारी सीजन में!

कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों ने इस साल त्योहारी सेल को लंबे वक्त तक चलाने का फैसला किया है। उद्योग सूत्रों के अनुसार, रिलायंस जियामार्ट के आने से अमेजन, फ्लिपकार्ट, बिगबास्केट, ग्रोफर्स समेत तमाम ई-कॉमर्स कंपनियों पर दबाब बढ़ा है। इसको देखते हुए कंपनियों ने सितंबर के आखिरी हफ्ते से ही त्योहारी सेल शुरू करने का फैसला किया है, जो दिवाली यानी नवंबर के दूसरे हफ्ते तक जारी रह सकता है।

ई-कॉमर्स कंपनियों की शीर्ष अधिकारियों के अनुसार, इस साल त्योहारी सीजन सेल लंबा चलेगा। इसकी शुरुआत किराने के सामान (ग्रॉसरी) के साथ होगी। इसके बाद धीरे-धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लयांस को शामिल किया जाएगा। इस दौरान बिग बिलियन डेज और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जैसे इवेंट का आयोजन किया जाएगा। इसमें ग्राहकों को मोबाइल, कपड़े और ग्रॉसरी के सामान पर बंपर छूट मुहैया कराई जाएगी।

किराना बाजार में दिलचस्प होगी जंग

रिलायंस की रिटेल विंग जियोमार्ट के आने से इस बार ग्रॉसरी बाजार में दिलचस्प प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए कि इस बार बाजार में सिर्फ बिगबास्केट या ग्रॉफर्स ही नहीं होंगे। अमेजन और फ्लिपकार्ट भी अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए रिटेल पर जोर दे रहे हैं। दोनों कंपनियों ने रिटेल बाजार में अपनी पकड़ बनाने के लिए बड़ा निवेश किया है।

फ्लिपकार्ट ने इस साल अपनी सेवाएं मैसूर, वारंगल, अलवर, अलीगढ़ और आगरा जैसे शहरों तक बढ़ाई हैं। पिछले ही महीने फ्लिपकार्ट ने 90 मिनट में ग्रॉसरी डिलीवरी की सेवा भी बेंगलुरु में शुरू की है। अमेजन ने भी दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु समेत छह शहरों में फ्रेश फूड के मामले में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इसी साल जून में कंपनी ने अमेजन पेंट्री या ग्रॉसरी और लोगों की जरूरत की चीजों पर 300 नगरों में फोकस बढ़ा दिया है।

डिलीवरी में जियोमार्ट सबसे आगे

रिलायंस जियोमार्ट का दावा है कि जुलाई में उसने 200 शहरों में औसतन 4 लाख ऑर्डर रोजाना डिलीवर किए हैं। कंपनी ने ये मुकाम लॉन्चिंग के दो महीने से भी कम वक्त में हासिल कर लिया। वहीं, बिगबास्केट ने लॉकडाउन के पहले चरण में तमाम प्रतिबंधों के बीच रोजाना औसतन 1.6 लाख ऑर्डर डिलीवर किए। ग्रॉफर्स ने रोजाना करीब 90 हजार ऑर्डर डिलीवर किए। जियोमार्ट का मॉडल अलग है, क्योंकि वह स्थानीय किराना स्टोर के जरिए अपनी डिलीवरी कर रहा है। वहीं सरी ओर ग्रॉफर्स और अमेजन अपनी पूरी सेवा खुद ही मुहैया कराते हैं।

कारोबार जगत को बड़ी उम्मीद

कारोबार जगत को आनेवाले त्योहारी सीजन से काफी उम्मीद है। कोरोना को लेकर व्यवसायियों को जो परेशानी हो रही है अब उन्हें लग रहा है कि दशहरा, ईद-उल-नबी, करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली, भइया दूज, छठ पूजा से लेकर क्रिसमस तक में खूब बिक्री होगी। बाजार का माहौल दशहरा से बदल जाएगा। ये त्योहार व्यापार जगत के लिए संजीवनी का काम करेगा। व्यवसायी भी त्योहारों को लेकर तैयारी में लग गए हैं। ऑटो सेक्टर में तो लोगों का उत्साह दिखने लगा है। ऐसे में धनतेरस पर गाड़ियों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। नवंबर व दिसंबर में शादी का भी लग्न है। बाजार में रौनक आना तय है। नए माल का ऑर्डर दे रहे कपड़ा व्यवसायी।

अर्थव्यवस्था में सुधार पूरी रफ्तार में नहीं पहुंचा, आर्थिक वृद्धि का इंजन बन सकता है पर्यटन क्षेत्र

आईपीटी नेटवर्क

कोरोना के चंगुल में फंसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों के बीच आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि RBI अर्थव्यवस्था के लिए जो भी कदम उठाने की आवश्यकता है, उसे लेने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार पूरी रफ्तार में नहीं पहुंचा है, यह धीरे-धीरे होगा। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र से काफी उम्मीद जताई है। शक्तिकांत दास का कहना है कि पर्यटन क्षेत्र आर्थिक वृद्धि का इंजन बन सकता है, क्षेत्र में बड़े पैमाने पर दबी मांग है, जिसका लाभ उठाने की जरूरत है। फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए आरबीआई प्रमुख ने कहा कि आर्थिक सुधार भी पूरी तरह से नहीं हुआ है। पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़ों से अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव दिख रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा का आर्थिक विकास में योगदान रहता है, ऐसे में नई शिक्षा नीति ऐतिहासिक है और नए युग के सुधारों के लिए जरूरी है। अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में निजी क्षेत्र को अनुसंधान, नवोन्मेष, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका

निभानी चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आरबीआई की ओर से लगातार बड़ी मात्रा में नकदी की उपलब्धता से सरकार से सरकार के लिए कम दर पर और बिना किसी परेशानी के बड़े पैमाने पर उधारी सुनिश्चित हुई है।बता दें आरबीआई का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है। वह भी तब जब कई रेटिंग एजेंसियों ने इस चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर में गिरावट का अनुमान लगाया है।

इससे पहले एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने सोमवार को कहा था कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9 प्रतिशत की गिरावट आएगी। पहले एसएंडपी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया था। पिछले सप्ताह दो अन्य वैश्विक रेटिंग एजेंसियों मूडीज और फिच ने भी भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाया था। मूडीज ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 11.5 प्रतिशत तथा फिच ने 10.5 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है। हालांकि, गोल्डमैन सैश का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 14.8 प्रतिशत की गिरावट आएगी।

घरेलू रेटिंग एजेंसियों की बात की जाए, तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 11.8 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है। क्रिसिल ने 9 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है। एडीबी ने कहा कि सरकार ने महामारी से उबरने के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपाय शुरू किए हैं। हालांकि, इससे ग्रामीण इलाकों के कमजोर वर्ग के लोगों को फायदा होगा, लेकिन इसके बावजूद निजी उपभोग बढ़ाने में मदद नहीं मिलेगी। एडीबी का अनुमान है कि विकासशील एशिया में 2020 में जीडीपी में 0.7 प्रतिशत की गिरावट आएगी। यह 1962 के बाद विकासशील एशिया में पहली गिरावट होगी। वहीं इस रुख के उलट चीन इस साल 1.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करेगा। 2021 में चीन की वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। विकासशील एशिया में जापान जैसे विकसित देश नहीं आते हैं।

बिल गेट्स ने की आधार-डिजिटल पेमेंट की तारीफ, कहा- जिस स्तर पर भारत ने ये किया, वैसा किसी देश में नही..

नयी दिल्ली। एजेंसी।

बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के संस्थापक बिल गेट्स ने एक बार फिर भारत के 'आधार' (Aadhaar) सिस्टम की तारीफ की है। उन्होंने कहा, भारत के लिए आधार और एनपीसीआई डिजिटल वित्तीय प्रणाली एक बार फिर विशाल संपत्ति साबित हुए हैं। इससे पहले भी उन्होंने आधार तकनीक की तारीफ करते हुए कहा था कि इससे गोपनीयता को लेकर कोई समस्या नहीं है। बिल गेट्स ने बातचीत में कहा, डिजिटल माध्यम से भुगतान करना एक शानदार चीज है। भारत ने जिस स्तर से यह किया, वैसा दुनिया के किसी दूसरे देश ने नहीं किया। उन्होंने कहा, भारत अपनी डिजिटल वित्तीय क्षमताओं का इस्तेमाल करने में सक्षम था। वहां आधार और एनपीसीआई भुगतान प्रणाली बहुत अच्छी तरह से काम करती है।

अन्य देशों को भी अपनाना चाहिए ये स्कीम

इससे पहले 2018 में भी एक कार्यक्रम में बिल गेट्स ने आधार सिस्टम की तारीफ की थी। उन्होंने कहा, इस आधार की तकनीक में गोपनीयता की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा था कि बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अन्य देशों तक ये तकनीक पहुंचाने के लिए फंड भी दिया है, क्योंकि ये अनुसरण करने योग्य है। गेट्स ने कहा था कि अन्य देशों को भी यह टेक्नोलॉजी अपनाना चाहिए।

क्या है एनपीसीआई

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन इंडिया (NPCI) एक गैर-लाभकारी कंपनी है, जिसका उद्देश्य भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली के साथ-साथ भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में 10 सबसे बड़े भारतीय बैंकों द्वारा स्थापित किया गया था।

रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाने को तैयारः शक्तिकांत दास

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास में लगे रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी, रिजर्व बैंक उसके लिये पूरी तरह तैयार है। उद्योग संगठन फिक्की के एक कार्यक्रम को संबोधित करते उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार अभी पूरी गति में नहीं पहुचा है, यह धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। उन्होंने निजी क्षेत्र को आगे बढ़कर अर्थव्यवस्था में सुधार की गति बढ़ाने में योगदान करने को कहा। दास ने कहा कि आरबीआई की ओर से लगातार बड़ी मात्रा में नकदी की उपलब्धता कराये जाने से सरकार के लिए कम दर पर और बिना किसी परेशानी के बड़े पैमाने पर उधारी सुनिश्चित हो पाई है। पिछले एक दशक में यह पहला मौका है जब उधारी लागत इतनी कम हुई है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक नकदी की उपलब्धता से सरकार की उधारी लागत बेहद कम बनी हुई है और इस समय बॉन्ड प्रतिफल पिछले 10 वर्षों के निचले स्तर पर हैं। दास ने कहा कि जीडीपी के आंकड़ों से अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रकोप का संकेत मिलता है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कोविड- 19 के बाद अर्थव्यवस्था की गति तेज करने के लिये निजी क्षेत्र को अनुसंधान एवं नवोन्मेष, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये कहा है। उन्होंने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र में व्यापक संभावनायें हैं और निजी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिये।

Covid-19

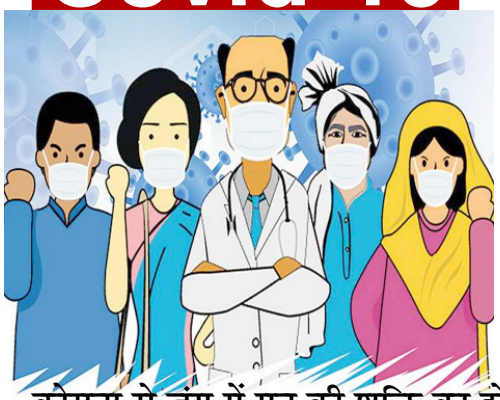

मन की शक्ति से जीतेंगे हम कोरोना से

10 बड़ी बातें

कोराना से जंग में मन की शक्ति का होना बहुत जरूरी है। ऐसे कई लोग हैं जो कोराना मरिज से मिले और फिर भी उन्हें कोरोना नहीं हुआ। ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें कोरोना हो गया और वे 4 दिन में या 7 दिन में ठीक हो गए। यह सब मन का खेल है परंतु आप सोचेगे ऐसा कैसे हो सकता है तो जानिए 10 बड़ी बातें।

1. मानना नहीं जानना : हमारा दिमाग और हमारा मन अर्थात बुद्धि और मन यदि इसने मान लिया की मैं बीमार हूं तब बीमारी नहीं होगी फिर भी आप बीमारी हो जाएंगे, क्योंकि दिमाग वही काम करना है जिसे मन स्वीकार कर लेता है। दिमाग शरीर का हिस्सा है और मन आपके सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। आप अंगूठा तभी हिला पाते हैं जबकि दिमाग के तंत्र को मन आदेश देता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए मन की शक्ति को समझे।

2. भय और चिंता : डॉक्टर मानते हैं कि भय और चिंता से आपका इम्युनिटी सिस्टम गड़बड़ा जाता है। कोरोना काल में सबसे जरूरी है इम्युनिटी पावर को बढ़ना। यदि आप भय और चिंता से घिरे रहेंगे तो इम्युनिटी बूस्टर लेने का कोई फायदा नहीं होगा। तनाव आपकी (आंतरिक) शक्ति और आत्मा की आवाज को दबा देता है। इसलिए इसे समझें और इससे दूर रहें। मन को मनोरंजन और रिश्तों में संवाद में लगाएं।

3. प्राणायाम और ध्यान : मन की शक्ति को बढ़ाने के दो ही सरल उपाय है पहला यह कि आप नियमित प्राणायाम और ध्यान करें। ध्यान करने से हमारी खोई ऊर्जा फिर से संचित होने लगती है और साथ ही अतिरिक्त ऊर्जा का संचय होता है जो हमें हर तरह के रोग और शोक से लड़ने में मदद करता है। ध्यान अनावश्यक कल्पना व विचारों को मन से हटाकर शुद्ध और निर्मल मौन में चले जाना है। विचारों पर नियंत्रण है ध्यान। प्राणायाम हामारे फेंफड़े और मस्तिष्क में ऑक्सिजन का लेवल बढ़ा देता है। भस्त्रिका प्राणायाम करें। भस्त्रिका का शब्दिक अर्थ है धौंकनी अर्थात एक ऐसा प्राणायाम जिसमें लोहार की धौंकनी की तरह आवाज करते हुए वेगपूर्वक शुद्ध प्राणवायु को अन्दर ले जाते हैं और अशुद्ध वायु को बाहर फेंकते हैं। इसे करने के पहले अनुलोम विलोम में परारंगत हो जाएं और फिर ही इसे करें।

4. शौच : योग के शौच को अपनाएं शौच अर्थात शुचिता, शुद्धता, शुद्धि, विशुद्धता, पवित्रता और निर्मलता। पवित्रता दो प्रकार की होती है- बाहरी और भीतरी। बाहरी या शारीरिक शुद्धता भी दो प्रकार की होती है। पहली में शरीर को बाहर से शुद्ध किया जाता है। इसमें मिट्टी, उबटन, त्रिफला, नीम आदि लगाकर निर्मल जल से स्नान करने से त्वचा एवं अंगों की शुद्धि होती है। दूसरी शरीर के अंतरिक अंगों को शुद्ध करने के लिए योग में कई उपाय बताए गए है- जैसे शंख प्रक्षालन, नेती, नौलि, धौती, गजकरणी, गणेश क्रिया, अंग संचालन आदि। भीतरी या मानसिक शुद्धता प्राप्त करने के लिए दो तरीके हैं। पहला मन के भाव व विचारों को समझते रहने से। जैसे- काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्यागने से मन की शुद्धि होती है। इससे सत्य आचरण का जन्म होता है।

6. निर्भिकता : गीता में कहा गया है। न जन्म तुम्हारे हाथ में है और न मृत्यु। न अतीत तुम्हारे हाथ में है और न भविष्य। तुम्हारे हाथ में है तो बस ये जीवन और ये वर्तमान। इसलिए जन्म और अतीत कर शोक मत करो और मृत्यु एवं भविष्य की चिंता मत करो। निर्भिक होकर बस कर्म करो। निष्काम कर्म करो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भविष्य है।

7. सोच : मनुष्य सोच से ही भयभीत होता है और सोच से ही रोगग्रस्त। आज हम जो हैं वह हमारे पिछले विचारों का परिणाम है और कल हम जो होंगे वह आज के विचारों का परिणाम होगा। वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि रोग की शुरुआत हमारे मन से होती है। मन में विचारों का झांझावत चलता रहता है। इन असंख?य विचारों में से ज्यादातर विचार निगेटिव ही होते हैं, क्योंकि निगेटिव विचारों को लाना नहीं पड़ता वह स्वतः ही आ जाते हैं। सकारात्मक विचार के लिए प्रयास करना होता है।

वैज्ञानिक कहते हैं मानव मस्तिष्क में 24 घंटे में लगभग 60 हजार विचार आते हैं। उनमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक विचारों का पलड़ा भारी है तो फिर भविष्य भी वैसा ही होगा और यदि ?मिश्रित विचार हैं तो मिश्रित भविष्य होगा। जो भी विचार निरंतर आ रहा है वह धारणा का रूप धर लेता है। ब्रह्मांड में इस रूप की तस्वीर पहुँच जाती है फिर जब वह पुनः आपके पास लौटती है तो उस तस्वीर अनुसार आपके आसपास वैसे घटनाक्रम निर्मित हो जाते हैं। विचार ही वस्तु बन जाते हैं। इसका सीधा-सा मतलब यह है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही भविष्य का निर्माण करते हैं। यही बात 'दि सीक्रेट' में भी कही गई है। इसी संदर्भ में जानें स्वाध्याय, धारणा और ईश्वर प्राणिधान के महत्व को।

8. नींद : भरपूर नींद और कसरत आपके दिमाग और मन को शक्ति ही प्रदान नहीं करते हैं बल्कि इम्युनिटी पावर भी डेवलप करते हैं। हमारी नींद सबसे बड़ी डॉक्टर है। चिंता और भय से घिरे मनुष्य की नींद कम हो जाती है। इसलिए जब भी सोने का मौका मिले जरूर सो जाएंगे भले ही झपकी लें लें। झपकी में वह क्षमता है जो 8 घंटे की नींद में भी नहीं है।

9. अन्न : कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। इसलिए ऐसा भोजन का चयन करो जो आपके शरीर और मन को सेहतमंद बनाए। भोजन और पान (पेय) से उत्पन्न उल्लास, रस और आनंद से पूर्णता की अवस्था की भावना भरें, उससे महान आनंद होगा। आयुर्वेद में लिखा है कि अन्न को आनंदित और प्रेमपूर्ण होकर ग्रहण करने से यदि वह जहर भी है तो अमृत सा लाभ देगा। अतः उत्तम भोजन को उत्तम भावनाओं के साथ ग्रहण करो। भोजन करने के समय किसी भी प्रकार से कहीं ओर ध्यान न भटकाएं। भोजन का पूर्ण सम्मान करके ही उसे ग्रहण करें।

10. कोरोना वायरस को समझें : कोरोना वायरस को समझें। यह कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। जिन्हें भी हुआ है वह ठीक हो गया है। हमारे देश में इस रोग से मरने वाले लोगों की संख्या प्रतिशत में बहुत कम है। जिन्होंने बगैर डरे समय पर जांच कराकर अपना इलाज प्रारंभ कर दिया है वह जल्द ही ठीक हो गया है। कोरोना से संक्रमित वही लोग हो रहे हैं जो गाइडलाइन को फालो नहीं कर रहे हैं। जहां तक सवाल डॉक्टर, नर्स, पैथोलॉजिस्ट, सफाईकर्मी, पुलिस और अन्य कोरोना वॉरियर का है तो वे आपकी सेवा करते हुए ही संक्रमित हुए हैं और उनमें से अधिकतर ठीक भी हो गए हैं। इसलिए डरे नहीं समझे, दो गज दूरी बनाकर रखें, मॉस्क लगाएं और समय-समय पर हाथ धोएं। यदि आप उपरोक्त नियमों का पालन करते हैं तो आपको कोरोना कभी नहीं होगा और यदि नहीं करते हैं तो आप देश के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं ऐसा माना जाएगा। आज नहीं तो कल यह वक्त भी गुजर जाएगा। जीतेगा वही जो अपने मन की शक्ति को बढ़ाएगा।

सर्वपितृ अमावस्या पर इस प्रार्थना से मांगें पूर्वजों से क्षमा

आश्विन माह की कृष्ण अमावस्या को सर्वपितृ मोक्ष श्राद्ध अमावस्या कहते हैं। यह दिन पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। अगर आप पितृपक्ष में श्राद्ध कर चुके हैं तो भी सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना जरूरी होता। सभी जाने और अनजाने पितरों हेतु इस दिन निश्चित ही श्राद्ध किया जाना चाहिए। इस दिन आप यदि अपने पितरों से क्षमा मांगने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु दो तरह के पाठ कर सकते हैं।

1. पितृ-सूक्तम् पाठ : पितृ-सूक्तम् पितृदोष निवारण में अत्यंत चमत्कारी मंत्र पाठ है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन विधिवत रूप से श्राद्ध करें और यह पाठ पढ़ें। श्राद्ध पक्ष में पितृ-सूक्त का पाठ संध्या के समय तेल का दीपक जलाकर करने से पितृदोष की शांति होती है, शुभ फल की प्राप्ति होती है और सर्वबाधा दूर होकर उन्नति की प्राप्ति होती है। इसे ही पितृ शांति पाठ भी कहते हैं।

2. रुचि कृत पितृ स्तोत्र : संपूर्व श्राद्ध पक्ष या सर्वपितृ अमावस्या को रूचि कृत पित्र स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है। इसे ही पितृ स्तोत्र का पाठ भी कहते हैं। अथ पितृस्तोत्र।

पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमाः
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्।
पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर?
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन।
यत्पूजितं मया देव! परिपूर्ण तदस्तु मे?

अर्थात हे प्रभु, मैं आपका आवाहन करना नहीं जानता हूं, ना ही विदा करना जानता हूं। पूजा के विधि-विधान भी मुझे नहीं मालूम हैं। कृपा करके मुझे क्षमा करें। मुझे मंत्र याद नहीं हैं और ना ही पूजा की क्रिया मालूम है। मैं तो ठीक से भक्ति करना भी नहीं जानता। फिर भी मेरी बुद्धि के अनुसार पूरे मन से पूजा कर रहा हूं, कृपया इस पूजा में हुई जानी-अनजानी गलतियों के लिए क्षमा करें। इस पूजा को पूर्ण और सफल करें।

टमाटर ने लगाया शतक, आलू ने पचासा, अब रुलाने लगा प्याज

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना काल में टमाटर अब कई जगहों पर शतक लगा चुका है। वहीं आलू 50 रुपये किलो बिकने लगा है जबकि प्याज के दाम एक हफ्ते में दोगुना होने से लोगों के आंसू निकल रहे हैं, हालांकि सरकार प्याज के रेट न बढ़ने पाए इसके लिए फौरी उपाय करते हुए सरकार ने सोमवार को प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। बावजूद इसे दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां तक टमाटर की कीमतों में उछाल की बात है तो देश के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश से टमाटर की आपूर्ति प्रभावित हुई है। यही वजह है कि माल्दा, एजल और इंफाल में इसकी खुदरा कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को देश में टमाटर की औसत खुदरा कीमत 50 रुपये थी।

मंत्रालय देशभर के 114 बाजार केंद्रों में 22 अनिवार्य वस्तुओं की कीमत पर नजर रखता है। इसमें आलू, टमाटर और प्याज शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में मंगलवार को आलू और प्याज की औसत कीमत 35 रुपये प्रति किलोग्राम रही। जबकि अधिकतम कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। आलू, प्याज और टमाटर लगभग हर भारतीय रसोई का हिस्सा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के चार महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में टमाटर की कीमत क्रमशः 63 रुपये, 68 रुपये, 80 रुपये और 50 रुपये प्रति किलोग्राम रही। हालांकि सब्जीवाले, फेरीवाले इत्यादि सरकारी दाम से ज्यादा पर ही टमाटर की बिक्री कर रहे हैं।। जबकि अधिकतम कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई।

बता दें रबी और खरीफ दोनों में प्याज को बोया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में ये फसल मई और नवंबर तक तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बंगाल में ये फसल इसके आगे-पीछे तैयार होती है। इस साल दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में टमाटर की फसल कम रहने की आशंका है। कोविड-19 महामारी के दौरान कीमतों को लेकर अनिश्चिता के चलते इस बार किसानों ने कम रकबे पर टमाटर की खेती की है। हर साल प्याज की कीमतें बढ़ने से रोकने के उपाय किए जाते हैं। प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया जाता है, प्याज के स्टॉक पर रोक लग जाती है। सरकारी एजेंसियां सस्ते दामों पर प्याज की बिक्री शुरू कर देती हैं। इस बार भी सरकार ने सोमवार को प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।

टोयोटा 2000 करोड़ से अधिक का करेगी निवेश, भारत में अपना विस्तार रोकने की बात से पीछे हटी

नई दिल्ली। एजेंसी

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) के वाइस- चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर ने मंगलवार को इस बात की पुष्टि की कि कंपनी अगले 12 माह के दौरान कंपनी वाहनों के इलेक्ट्रिक कलपुर्जों और प्रौद्योगिकी में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी। उन्होंने कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के बयान को नकारते हुए बात कही। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि कंपनी भारत में ऊंचे करों को देखते हुए अपना विस्तार रोक रही है। कंपनी ने एक अलग वक्तव्य में यह भी कहा था कि उसकी प्राथमिकता भारत में अपनी मौजूदा क्षमता को इस्तेमाल करने की है, जिसमें समय लगेगा।

कंपनी भारत में अपना विस्तार रोकने की कही थी बात

टीकेएम के वाइस चेयरमैन और पूर्णकालिक निदेशक शेखर विश्वनाथन शेखर ने ब्लूमबर्ग के साथ एक साक्षात्कार में कहा था कि कंपनी भारत में अपना विस्तार रोक देगी।उन्होंने यह कहते हुये भविष्य के निवेश को भी खारिज कर दिया था कि भारत में कारों और मोटरबाइक पर कर इतने अधिक हैं कि कंपनी आगे बढ़ना काफी मुश्किल देखती है। इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया में केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके कहाः ''टोयोटा कंपनी भारत में निवेश रोक रही है इस प्रकार का समाचार गलत है। विक्रम किर्लोस्कर ने स्पष्ट किया है कि टोयोटा अगले 12 माह में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी।

कंपनी बोली-हम भारत के भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध हैं

मंत्री के कथन की पुष्टि करते हुये किर्लोस्कर ने भी ट्वीट कर कहा, ''बिल्कुल, हम घरेलू ग्राहकों और निर्यात के लिये इलेक्ट्रिक कलपुर्जों और प्रौद्योगिकी में 2,000 करोड़ से अधिक निवेश कर रहे हैं। हम भारत के भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध हैं और समाज, पयार्वरण, कौशल एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हर संभव प्रयास करते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी को लगता है कि मांग बढ़ रही है और बाजार में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। ''भारत में वहनीय मोबिलिटी का भविष्य काफी मजबूत है और टोयोटा को इस यात्रा का हिस्सा होने पर गर्व है। कंपनी के बेंगलूरू के निकट बिडाडी में दो कारखाने हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 3.10 लाख इकाइयों की है। टीकेएम जापानी कंपनी टोयोटा मोटर कंपनी और किर्लोस्कर समूह के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी है।

वृद्धि में मदद के लिये एक लाख करोड़ रुपये मूल्य की शत्रु संपत्तियां बेचने की सलाह

मुंबई।एजेंसी

सरकार को कोविड- 19 से प्रभावित आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और मौजूदा बढ़े खर्च को पूरा करने के लिये शत्रु संपत्ति को बेचने पर गौर करना चाहिये जो एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंश कालिक सदस्य नीलेष शाह ने सोमवार को यह सुझाव दिया। शाह ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने 1965 की लड़ाई के बाद शत्रु संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिये कानून बनाये। पाकिस्तान इस तरह की समूची संपत्ति को 1971 में ही बेच चुका है लेकिन भारत इस मामले में उससे 49 साल पीछे चल रहा है। आईएमसी के वेबिनार को संबोधित करते हुये शाह ने कहा, "आपको सरकारी संपत्ति का मौद्रीकरण करना चाहिये ताकि आगे खर्च करने के लिये आपके पास धन उपलब्ध हो।" नीलेष शाह कोटक म्युचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। उन्होंने कहा कि इस शत्रु संपत्ति का मूल्य तीन साल पहले एक लाख करोड़ रुपये आंका गया था। उन्होंने कहा कि इस तरह की संपत्तियों को बेचकर अतिक्रमण हटाने और मालिकाना हक की विसंगतियों को दूर करने का यह सबसे बेहतर समय है। शाह ने कहा कि इस तरह की 9,404 संपत्तियां हैं जो कि 1965 में सरकार द्वारा नियुक्त कस्टोडियन के अधीन की गई थीं। सुस्त पड़ती आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के तौर तरीकों पर पूछे गये सवाल पर शाह ने कहा, "इन संपत्तियों को बेच डालिये और एक लाख करोड़ रुपये की राशि प्राप्त कर लीजिये, इससे आपके खर्चे पूरे हो जायेंगे।" इसी वेबिनार को संबोधित करते हुये स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड के मुख्य निवेश अधिकारी नवनीत मुनोट ने कहा कि आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिये मामले को पूरी तरह से मौद्रिक प्राधिकरणों के ऊपर छोड़ने के बजाय राजकोषीय उपाय करने की जरूरत है। शाह ने इस मौके पर भारतीयों के पास उपलब्ध बिना हिसाब किताब वाले सोने का भी इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे नये व्यय और निवेश के लिये 300 अरब डालर तक उपलब्ध हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक भारतीयों के पास 25,000 टन सोना रखा हुआ है। एक ऐसी योजना लाई जा सकती है जो इसमें से कम से कम दस प्रतिशत सोने को निकाल सके। इससे कर के रूप में 50 अरब डालर प्राप्त होंगे और 150 अरब डालर निवेश और खर्च के लिये उपलब्ध होंगे। शाह ने स्वर्ण वित्त कंपनियों के काम की सराहना करते हुये कहा उन्होंने सोने को उत्पादक कार्यों में लगाया लेकिन कहा कि उनके इस काम को और व्यापक बनाने की जरूरत है। शाह और मुनोट दोनों ने कहा कि नकदी की उपलब्धता ही है जो कि शेयर बाजार में मौजूदा तेजी का कारण बनी हुई है। पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में करीब एक चौथाई की गिरावट के बावजूद शेयर बाजार में तेजी जारी है, इसके पीछे उपलब्ध तरलता बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि बाजार भविष्य की बड़ी उम्मीदों से देख रहा है जिससे की बाजार में तेजी जारी है।

निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं की कुल क्षमता 59,810 मेगावाट

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश में 59,810 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता वाली परियोजनायें निर्माणाधीन हैं। इनमें से 23,730 मेगावाट बिजली परियोजनायें निजी कंपनियों द्वारा विकसित की जा रही हैं। यह जानकारी मंगलवार को संसद को दी गई। बिजली मंत्री आर के सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि केंद्रीय क्षेत्र के तहत निर्माणाधीन परियोजनाओं की कुल क्षमता 18,320 मेगावाट की है, जबकि राज्यों के अंतर्गत आने वाली 17,760 मेगावाट की परियाजनायें हैं। वहीं, निर्माणाधीन बड़े जलविद्युत (25 मेगावाट से ऊपर) परियोजनाओं की क्षमता लगभग 14,014 मेगावाट है।

घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या अगस्त में रही 28.32 लाख, पिछले साल से 76 प्रतिशत कमः डीजीसीए

नयी दिल्ली। एजेंसी

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के मुताबिक इस साल अगस्त में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 28.32 लाख रही। यह अगस्त 2019 के मुकाबले 76 प्रतिशत कम रही है। नागर विमानन क्षेत्र नियामक डीजीसीए ने बुधवार को कहा कि 59.4 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ इंडिगो के यात्रियों की संख्या 16.82 लाख रही, जबकि 13.8 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ स्पाइसजेट से 3.91 लाख यात्रियों ने उड़ान भरी। इसके बाद एअर इंडिया, एयरएशिया इंडिया, विस्तार और गोएयर के यात्रियों की संख्या क्रमशः 2.78 लाख, 1.92 लाख, 1.42 लाख और 1.33 लाख रही। पिछले महीने डीजीसीए ने जुलाई में 21.07 लाख यात्रियों के घरेलू हवाई यात्रा करने के आंकड़े जारी किए थे। डीजीसीए ने बुधवार को कहा कि अगस्त में छह में से पांच प्रमुख विमानन कंपनियों के सीटों के भरने की दर 58 से 69 प्रतिशत रही। वहीं स्पाइसजेट के सीटें भरने की दर 76 प्रतिशत रही। डीजीसीए ने कहा, "लॉकडाउन खुलने के बाद अगस्त में मांग बढ़ने से विमानन कंपनियों की सीटें भरने की दर सुधरी है।" इसी तरह विस्तार, इंडिगो, एयरएशिया इंडिया, गोएयर और एअर इंडिया की सीटें भरने की दर क्रमशः 68.3 प्रतिशत, 65.6 प्रतिशत, 64.4 प्रतिशत, 61 प्रतिशत और 58.6 प्रतिशत रही। बेंगलुरू, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई जैसे प्रमुख हवाईअड्डों पर समयबद्ध तरीके से उड़ान भरने के मामले में इंडिगो का प्रदर्शन अगस्त में सबसे बेहतर रहा। कंपनी की 98.5 प्रतिशत उड़ानें अपने तय समय पर संचालित हुईं। वहीं 97.6 प्रतिशत और 95.9 प्रतिशत उड़ानें समय से संचालित कर इस मामले में एयरएशिया इंडिया और विस्तार क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। देश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च से लॉकडाउन किया गया। इससे देश में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन पर रोक रही। करीब दो महीने बाद 25 मई से घरेलू उड़ानों को दोबारा चालू किया गया। वहीं विशेष समझौतों और वंदे भारत मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन भी हो रहा है।

कहां-कैसे खर्च हो रहा है आत्मनिर्भर भारत पैकेज का 20 लाख करोड़

वित्त मंत्रालय ने दिया लेखा-जोखा

नई दिल्ली। एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्रि मोदी ने भारत में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 12 मई 2020 को 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की थी। कहा गया था कि यह पैकेज भारत की उ3इ के 10% के बराबर है। इतने बड़े पैकेज का पैसा कहां और कैसे खर्च होगा, इसकी डिटेल की मांग काफी पहले से हो रही है। अब वित्त मंत्रालय ने इसका एक लेखाजोखा पेश किया है। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालयों ने आत्मिनर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक पैकेज से संबंधित घोषणाओं को तुरंत लागू करना शुरू कर दिया था। मंत्रालयों द्वारा आत्मणनिर्भर भारत पैकेज की मौजूदा योजनाओं के कार्यान्वयन में अब तक हुई प्रगति इस तरह है।

1. नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी राशिः जारी बयान के मुताबिक 28 अगस्त 2020 तक 25,000 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। विशेष लिक्विडिटी सुविधा (एसएलएफ) के तहत 5000 करोड़ रुपये की शेष राशि छोटी एनबीएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई के लिए आरबीआई द्वारा नाबार्ड को आवंटित की गई। नाबार्ड इसे शीघ्र ही शुरू करने के लिए परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे रहा है। इसके अलावा नाबार्ड ने दो एजेंसियों एवं बैंकों के साथ मिलकर 'संरचित वित्त और आंशिक गारंटी योजना' भी शुरू की है, ताकि ऋणदाताओं से कर्ज प्राप्त करने में बिना रेटिंग वाली एनबीएफसी/एमएफआई की मदद की जा सके।

इस तरह की दो एजेंसियां और बैंकों के साथ मिलकर तैयार की गई इस व्यआवस्था से उन छोटे एमएफआई के लिए ऋण की पात्रता 5-6 गुना बढ़ जाएगी, जिन्हेंस कोई भी रेटिंग प्राप्तय नहीं है। जब एक बार इस योजना के लिए निर्धारित समस्तज 500 करोड़ रुपये का इस्तेगमाल सही ढंग से हो जाता है, तो इन छोटी एनबीएफसी/एमएफआई द्वारा 2500 से 3000 करोड़ रुपये तक की ऋण प्राप्ति की परिकल्पना की जाती है। यह सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों, विशेषकर महिलाओं तक पहुंचने में एक गेम चेंजर साबित होगा।

2. श्एई और व्यक्तियों को नए सिरे से कर्ज देने के लिए ँइण, प्इण और श्इइ के लिए 45,000 करोड़ रुपये की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0: वित्त मंत्रालय के बयान के मुताबिक 28 अगस्तर 2020 तक बैंकों ने 25,055.5 करोड़ रुपये के पोर्टफोलियो की खरीद को मंजूरी दे दी है और वे वर्तमान में अतिरिक्त 4,367 करोड़ रुपये के लिए अनुमोदन/बातचीत की प्रक्रिया में हैं।

3. एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रुपये की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ने भी अच्छी प्रगति की है। योजना को लागू करने के लिए एसबीआईकैप को एक एसपीवी स्थापित करने का जिम्मौ सौंपा गया था। यह योजना 1 जुलाई, 2020 को जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से शुरू की गई थी। उसी दिन नियामक आरबीआई ने भी इस योजना पर एनबीएफसी और एचएफसी को एक सर्कुलर जारी कर दिया था।

11 सितंबर 2020 तक 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 10590 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। 783.5 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के लिए 6 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।

4. श्एई सहित कारोबारियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का गारंटी-मुक्त ूर्दूर्सूम लोनः व्यवसाय को राहत देने के लिए 29 फरवरी 2020 तक बकाया ऋण के 20इ के बराबर अतिरिक्त कार्यशील पूंजी वित्त रियायती ब्या ज दर पर सावधि ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह 25 करोड़ रुपये तक के बकाया ऋण और 100 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली उन इकाइयों के लिए उपलब्ध होगा, जिनके खाते स्टैंडर्ड हैं। इन इकाइयों को स्वयं की ओर से कोई गारंटी या जमानत प्रदान नहीं करनी होगी। इस राशि पर 100इ गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाएगी जो 45 लाख से भी अधिक एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपये की कुल लिक्विडिटी प्रदान करेगी।

20 मई 2020 को कैबिनेट की मंजूरी लेने के बाद वित्तीय सेवा विभाग ने 23 मई को योजना के लिए परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए और आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) फंड 26 मई को पंजीकृत किया गया। व्य वसाय के लिए व्यक्तिगत ऋणों को शामिल करने, बकाया ऋण सीमा को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये करने और वार्षिक कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये करने के लिए 4 अगस्त को दिशा-निर्देशों में संशोधन किए गए।

10 सितंबर 2020 तक 42,01,576 कर्जदारों को 1,63,226.49 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण राशि मंजूर की गई है। 10 सितंबर 2020 तक 25,01,999 कर्जदारों को 1,18,138।64 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। यह जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के शीर्ष 23 बैंकों द्वारा दी गई है।

5. आयकर रिफंडः 1 अप्रैल 2020 से लेकर 8 सितंबर 2020 तक की अवधि के बीच 27।55 लाख से ज्याशदा करदाताओं को 1,01,308 करोड़ रुपये से भी अधिक के रिफंड जारी किए गए हैं। 25,83,507 मामलों में 30,768 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड जारी किए गए हैं और 1,71,155 मामलों में 70,540 करोड़ रुपये के कॉरपोरेट टैक्स रिफंड जारी किए गए हैं। दरअसल उन समस्त5 मामलों में 50 करोड़ रुपये तक के सभी कॉरपोरेट टैक्स रिफंड जारी कर दिए गए हैं, जहां भी देय थे। अन्य रिफंड प्रक्रियाधीन हैं।

भारत के लिए खुशखबरी

नवंबर तक आ सकती है कोरोनावायरस की वैक्सीन

मुंबई। एजेंसी

रूस के सॉवरेन वेल्थ फंड The Russian Direct Investment Fund (RDIF) ने भारत में कोरोनावायरस की वैक्सीन Sputnik V के क्लीनिकल ट्रायल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डॉ. रेड्डीज लैब से हाथ मिलाया है। दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौते के मुताबिक RDIF भारतीय कंपनी को वैक्सीन की 10 करोड़ डोज की सप्लाई करेगी। RDIF के सीईओ Kirill Dmitriev ने ईटी को बताया कि Sputnik V वैक्सीन एडिनोवायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित है और अगर इसका ट्रायल सफल होता है तो यह नवंबर तक भारत में उपलब्ध होगी।

RDIF की साथ ही चार अन्य भारतीय कंपनियों के साथ भी बातचीत चल रही है जो भारत में यह वैक्सीन बनाएंगी। RDIF ने एक बयान में कहा कि उसके और डॉ. रेड्डीज के बीच हुआ समझौता इस बात का प्रमाण है कि विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच यह समझ बढ़ रही है कि कोरोनावायरस के लोगों को बचाने के लिए कई वैक्सीन पर काम करना जरूरी है। कंपनी ने कहा कि रूसी वैक्सीन एडिनोवायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित है और दशकों तक इस पर 250 से अधिक क्लिनिकल स्टडीज हो चुकी हैं। इसे सुरक्षित पाया गया है और इससे दीर्घकालिक दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिले हैं।

कोरोनावायरस के खिलाफ कारगर हथियार

डॉ. रेड्डीज के सीईओ जीवी प्रसाद ने एक बयान में कहा कि इस वैक्सीन के फेस 1 और फेस 2 ट्रायल के नतीजे उत्साहजनक रहे हैं और भारतीय नियामकों के मानकों को पूरा करने के लिए हम भारत में इसका फेज 3 ट्रायल करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में Sputnik V वैक्सीन विश्वसनीय विकल्प हो सकती है। सितंबर में Lancet में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक यह वैक्सीन सुरक्षित है। फेज 1 और फेज 2 के आंकड़ों के मुताबिक इसने सेल्युलर और एंटीबॉडी रिस्पांस जेनरेट किया। फेज 3 ट्रायल के नतीजे अक्टूबर-नवंबर में प्रकाशित होने की उम्मीद है। रूस ने सबसे पहले कोरोनावायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया था। उस पर आरोप लगे थे कि उसने जरूरी प्रोटोकॉल का पालन किए बिना जल्दबाजी की। इस बारे में Dmitriev ने कहा कि एडिनोवाइरस प्लेटफॉर्म mRNA वैक्सीन की तुलना में काफी सुरक्षित होती है। पश्चिमी देशों की अधिकांश कंपनियां mRNA वैक्सीन बना रही हैं।

भारत महामारी से उबरने के बाद सुधारों के बल पर उच्च वृद्धि दर के रास्ते पर लौटेगाः सीईए

चेन्नई। एजेंसी

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) कृष्णमूर्ति सुबमणियम ने मंगलवार को भरोसा जताया कि देश कोविड-19 महामारी से पार पाने के बाद सरकार के आर्थिक सुधारों के जरिये उच्च वृद्धि दर के रास्ते पर लौटेगा। उद्योग मंडल सीआईआई की तमिलनाडु इकाई द्वारा आयोजित कनेक्ट- 2020 सम्मेलन में भाग लेते हुए उन्होंने कहा, ''केंद्र सरकार द्वारा घोषित सुधारों का जब असर सामने आएगा, निश्चित रूप से हम उच्च वृद्धि के रास्ते पर होंगे।'' सुब्रमणियम ने कहा, ''महामारी के समाप्त होने के बाद सुधारों एवं केंद्र सरकार के अन्य उपायों के जरिये भारत उच्च आर्थिक वृद्धि दर के रास्ते पर लौटेगा।'' उन्होंने कहा कि सीमेंट, इस्पात, रेलवे माल ढुलाई और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्र पहली बार जुलाई 2019 से सकारात्मक दायरे में थे। सीईए ने कहा, ''अगर आप 'परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स' (पीएमआई) देखें, विनिर्माण और सेवा दोनों पीएमआई में तीव्र वृद्धि हुई है।'' उन्होंने कहा लेकिन यह कहना कि पिछली 12 तिमाहियों से जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में गिरावट दर्ज की जा रही है, 'गलत' है। इससे पहले, सुब्रमणियम ने कहा कि केंद्र राज्यों से श्रम कानूनों में सुधारों के लिये आग्रह कर रहा है। श्रम कानून राज्यों के दायरे में है और उनमें से कुछ कानून 100 साल से अधिक पुराने हैं। उन्होंने कहा कि कई पुराने श्रम कानूनों में वेतन और मजदूरी की परिभाषा अलग-अलग तरीके से की गयी हैं, इससे अनुपालन संबंधी समस्या होती है। सीईए ने कहा कि कई राज्य श्रम कानूनों में बदलाव की योजना बना रहे हैं।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।